बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 47 ● नई दिल्ली ● वीरवार 27 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

सीईओ कार्यालय में बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त, बताया सुरक्षा में गंभीर चूक

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर बीएलओ के विरोध प्रदर्शन को गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के कार्यालय की सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं लग रही है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की वजह से बीएलओ बहुत ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर बूथ-लेवल ऑफिसर्स के एक समूह ने मंगलवार शाम तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर 30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया।

संविधान की आत्मा ने प्रमाणित किया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को सभी से 'विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और कहा कि हमारे संविधान की आत्मा ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा। संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संवाद, बहस और चर्चा को अपनाएं। उन्होंने कहा, ''लोगों के योगदान के बिना कोई भी देश ऐसे ही महान नहीं बन सकता। हमें कर्तव्यबोध के साथ अपनी-अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी। उपराष्ट्रपति ने कहा, ''इस दिन हमारे शानदार संविधान के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यह है कि हम इसके मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लें। जन प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, ''चाहे संसद हो या राज्य विधानसभाएं या स्थानीय निकाय, यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम लोगों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संवाद, बहस और चर्चा को अपनाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा, ''हमारे संविधान निर्माताओं की इसी भावना के अनुरूप हमें अब इस अमृत काल में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक सोच के साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। उन्होंने कहा, ''वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य में हम सभी को जीवन के कई क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी सुधार, न्यायिक सुधार और वित्तीय सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र भारत के लिए कोई नयी अवधारणा नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है कि उत्तर में वैशाली जैसे स्थानों में लोकतंत्र मौजूद था, जबकि दक्षिण में चोल शासकों ने ''कुदावोलाई प्रणाली अपनाई थी। उन्होंने कहा, ''इसलिए हम भारत को

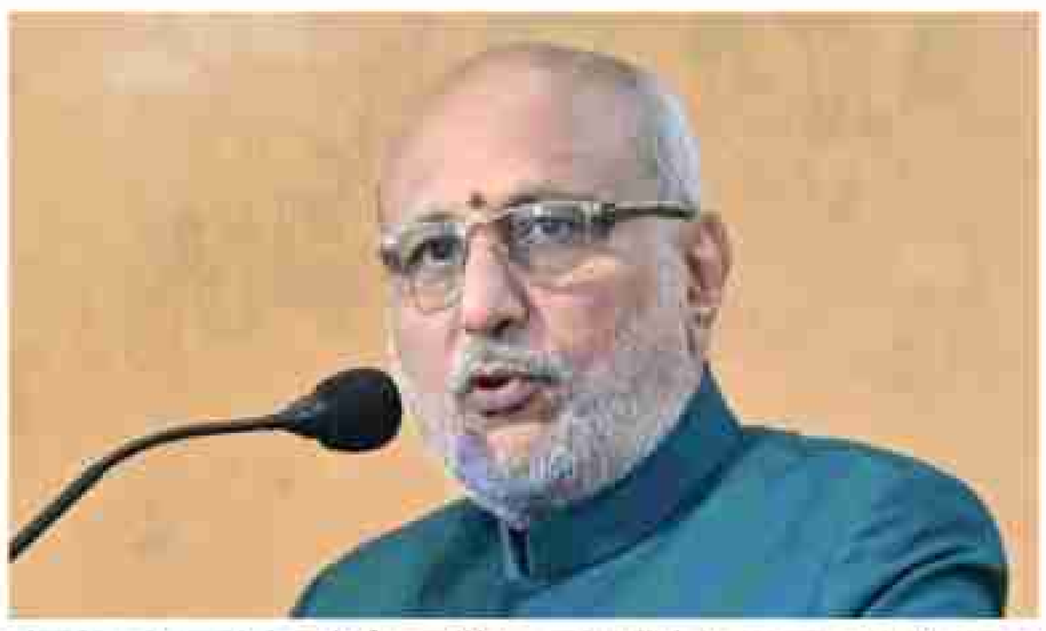

लोकतंत्र की जननी कहते हैं। उन्होंने कहा, ''नागरिकों के सचेत योगदान के बिना कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि जीएसटी के रूप में 'एक राष्ट्र-एक कर प्रणाली ने व्यापार करने में आसानी के अलावा लोगों की समृद्धि में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ''इसने रातोंरात देश की जटिल बहु-कर प्रणालियों और सभी कमियों को हटाने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे यह साबित हुआ कि सरकार को आम आदमी पर पूरा भरोसा है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे जनधन और आधार ने करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है, जबकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभ देश के सबसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि सरकार और लाभार्थी के बीच कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राधाकृष्णन ने कहा, ''हमारा संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों के सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, ''हम सभी को अपने संविधान पर गर्व है; इसमें समावेशी भावना निहित है। इसकी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, लिंग, भाषा, क्षेत्र या धर्म का हो, उसे भारत की धरती पर उचित स्थान मिले। राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान का जन्म बुद्धि, अनुभव, बलिदान, आशाओं और आकांक्षाओं से हुआ है। उन्होंने कहा, ''हमारे संविधान की आत्मा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा। बी आर आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दुर्गा बाई देशमुख और अन्य नेताओं के योगदान की सराहना करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने संविधान को इस तरह से तैयार किया कि ''इसके हर पृष्ठ में हमें अपने राष्ट्र की आत्मा दिखाई देती है। उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है और उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने दावा किया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से 100 करोड़ लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है और ''हमने असंभव को संभव बना दिया है। राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि भारत में हर नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों में लोगों की भारी भागीदारी ने लोकतंत्र में उनकी आस्था को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में मतदाताओं विशेषकर महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी एक बहुत ही अच्छा संकेत है।

55 मिनट ही वॉक कर सका, सुबह तक परेशान रहा..., दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर बोले सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली ।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें शाम के वक्त वॉक करने में परेशानी हो रही है. बुधवार (26 नवंबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा भी उठा. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कल शाम को वॉक के बाद उन्हें प्रदूषण के चलते बहुत असुविधा महसूस हुई. इससे पहले भी वह 2 दिन वॉक पर नहीं जा पाए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने 55 मिनट ही वॉक की और सुबह तक उनको परेशानी रही. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बातें तब कहीं जब एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के लिए पेश सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने 2 दिसंबर की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति मांगी. 2 दिसंबर को केरल एसआईआर पर सुनवाई होनी है. उन्होंने प्रदूषण का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि कोर्ट को फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही काम करना चाहिए. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह बार एसोसिएशन और जजों से इस पर विचार-विमर्श करेंगे. सबकी सहमति से कोई फैसला लिया जाएगा. दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई जगहों पर एक्यूआई 350 के भी पार पहुंच चुका है और 12 दिनों से हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई को फिलहाल 2 हिस्सों में बांट दिया है. पहला मुख्य मुद्दा जिसमें एसआईआर की वैधता पर सुनवाई होगी और दूसरा राज्यों के स्थानीय मसले जिनके चलते वहां की कुछ राजनीतिक पार्टियां एसआईआर टालने की मांग कर रही हैं. राज्यों के स्थानीय मसलों पर सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं. केरल का मामला 2 दिसंबर, तमिलनाडु का 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल का 9 दिसंबर को सुना जाएगा. कोर्ट ने इन मामलों के याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि अगर उसे जरूरी लगा तो वह ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन की तारीख आगे बढ़ा देगा. चुनाव आयोग की तरफ से तय शेड्यूल के मुताबिक स्ह्रक्र फॉर्म 4 दिसंबर तक भरे जाने हैं और ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को होना है.

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज, आप बोली- एक्यूआई के डेटा में हेराफेरी कर रही सरकार

नई दिल्ली । प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. आम आदमी पार्टी (आप) ने राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के डेटा में हेराफेरी कर रही है और वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश कर रही है. सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि दिल्ली के लोग साफ हवा के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना दबाने की नीयत से प्रदूषण पर बात करने वालों को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि शहर में हालात इतने खराब हैं कि लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप पर भी प्रदूषण पर चर्चा करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार इस वर्ष अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में तेजी से बढ़ी है. इसके बावजूद सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. आम आदमी पार्टी ने सुझाव दिया कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार को उत्तर भारत के सभी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश को एक साथ बैठाकर समाधान तलाशना चाहिए. पार्टी ने कहा कि जब दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट बंद किए जा सकते हैं, तो पड़ोसी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है. आप के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि पिछले नौ महीनों में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया. उनका दावा है कि सड़कों की खराब स्थिति, धूल और निर्माण सामग्री के अनियंत्रित प्रसार ने वायु गुणवत्ता को और खराब कर दिया है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है. कुलदीप कुमार ने कहा कि जब दिल्ली में आप की सरकार थी, तब ओड-ईवन योजना, रेड लाइट ऑन-इंजन ऑफ कैम्पेन और क्लीन दिल्ली जैसे अभियानों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार न सिर्फ इन पहलों को रोक चुकी है बल्कि अब यह दावा कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण है ही नहीं.

मानवाधिकार आयोग का रेलवे को नोटिस: ट्रेनों में हलाल मांस परोसने पर उठने लगे सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा गरमाया

नई दिल्ली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भारतीय रेलवे द्वारा मांसाहारी व्यंजनों में केवल हलाल-प्रमाणित मांस परोसे जाने से संबंधित एक शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि केवल हलाल मांस परोसने की प्रथा हिंदुओं, सिखों और अनुसूचित जाति समुदायों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, खासकर मांस व्यापार से जुड़े लोगों पर। तर्क दिया गया कि इस बहिष्कार से उनकी आजीविका को नुकसान पहुँचता है और यात्रियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन के विकल्प नहीं मिलते। एनएचआरसी ने कहा कि यह प्रथा भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों, जिनमें अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(जी), 21 और 25 शामिल हैं, का संभावित रूप से उल्लंघन करती है, जो समानता, गैर-भेदभाव, पेशे की स्वतंत्रता, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। आयोग ने भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप सभी धर्मों के लोगों के भोजन विकल्पों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।

ऐतिहासिक टाउन हॉल मीटिंग का सफल आयोजन

नई दिल्ली (इंद्रजीत सिंह)सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली ज़ोन ने एक भव्य और ऐतिहासिक टाउन हॉल मीटिंग का सफल आयोजन किया, जिसमें विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा कार्यक्रम दिल्ली ज़ोन के ज़ोनल हेड, सिसराम तुंदवाल के सशक्त नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजन स्थल ऊर्जा, एकजुटता और सकारात्मक माहौल से भर गया था, जहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों ने बैंक की सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री कल्याण कुमार की

उपस्थिति रही। उनके आगमन पर सभागार तालियों से गूंज उठा। अपने प्रेरक और उत्साहवर्धक संबोधन में उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर बैंक के प्रदर्शन को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँ। उन्होंने नवाचार, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग और टीमवर्क को बैंक की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित अधिकारी और कर्मचारी हैं।

कार्यक्रम के दौरान एक भावनात्मक क्षण तब आया जब यह आह्वान किया गया—:सभी सेंट्रलाइट्स कृपया हमारे प्रिय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विजय के लिए खड़े हों!÷ इस घोषणा के साथ पूरा सभागार एकजुट होकर खड़ा हो गया और हॉल गर्व और उत्साह की अनोखी भावना से भर उठा। इस दृश्य ने संगठन के प्रति कर्मचारियों की गहरी निष्ठा और अपनापन साफ झलका दिया। टाउन हॉल मीटिंग में प्रदर्शन सुधार, ग्राहक संतुष्टि, शाखाओं की दक्षता बढ़ाने और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बैंक के लक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन उप महाप्रबंधक, पी. सी. खुराना के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने टाउन हॉल के सफल आयोजन के लिए नेतृत्व टीम को बधाई देते हुए बैंक की प्रगति में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। श्री खुराना ने कहा कि दिल्ली ज़ोन की वास्तविक मजबूती इसकी टीम की एकजुटता, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित है।

भारतीय परम्पराओं का अनुपालन कर हमें संयुक्त परिवारों को बचाना होगा

प्रह्लाद सबनानी ।

भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने, कम करने अथवा प्रभावित करने के उद्देश्य से दरअसल, चार शक्तियों ने हाथ मिला लिए हैं। ये चार शक्तियां हैं, कट्टरवादी इस्लाम, प्रसारवादी चर्च, सांस्कृतिक मार्क्सवाद एवं वैश्विक बाजार शक्तियां। हालांकि उक्त चारों शक्तियों की अन्य देशों में आपसी लड़ाई है परंतु भारत के मामले में यह एक हो गई हैं और भारत में यह आपस में मिलकर भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी संदर्भ में आज वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध कई झूठे विमर्श भी गढ़े जा रहे हैं। हाल ही के समय में इस प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। विमर्शों के माध्यम से जनता के मानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। विमर्श सत्य, अर्द्धसत्य अथवा झूठ भी हो सकता है। भारत के बारे में पूरे विश्व में धारणा है कि यहां आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा रही है। परंतु, अब पूरे विश्व में विशेष रूप से भारत के संदर्भ में पुराने विमर्श टूट रहे हैं और नित नए विमर्श गढ़े जा रहे हैं। भारत चूंकि, हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बन कर उभर रहा है, भारत की यह प्रगति कुछ देशों को रास नहीं आ रही है एवं यह सभी मिलकर भारत के सम्बन्ध में झूठे विमर्श गढ़ रहे हैं। पश्चिमी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा है, यह पश्चिमी सोच, चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है। इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है इससे भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग में संयम बरता जाता है एवं उत्पादन में बहुलता होने की विचारधारा पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अन्य कोई भी भूखा ना सोय, यह भारतीय विचारधारा है। भारतीय सनातन संस्कृति की विचारधारा के ठीक विपरीत आज वैश्विक बाजार शक्तियां भारत में भी उपभोक्तावाद को फैलाने का प्रयास कर रही हैं। विशेष रूप से दीपावली एवं रक्षाबंधन जैसे शुभ त्यौहारों के अवसर पर कुछ मीठा हो जाए जैसे विज्ञापन देकर यह विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जाता है कि भारतीय मिठाइयों एवं व्यंजनों जैसे जलेबी, इमरती तथा दूध एवं खोए से बनी मिठाइयां खाने से मधुमेह का रोग हो जाता है, अतः सदियों से भारत में उपयोग हो रहे इन स्वादिष्ट व्यंजनों के स्थान पर कैडबरी चाकलेट अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, जिसका अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार, भारी भरकम राशि खर्च कर, विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित मीठे पदार्थों को, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय समाज के मानस पर उतारने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, विभिन्न भारतीय त्यौहारों के समय वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा यह भी कहा कर कि, दीपावली के शुभ अवसर पर जलाए जाने वाले फटाके पर्यावरण का नुकसान करते हैं; होली पर्व पर भारी मात्रा में पानी की बर्बादी की जाती है; महाशिवरात्रि पर्व पर दूध की बर्बादी की जाती है; माई बॉडी माई चॉइस; हमको भारत में रहने में डर लगता है; आदि विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर पश्चिमी देशों द्वारा आज भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित हिन्दू परम्पराओं पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कारों के अनुसार भारत में कुटुंब को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है एवं भारत में संयुक्त परिवार इसकी परिणति के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु, पश्चिमी आर्थिक दर्शन में संयुक्त परिवार लगभग नहीं के बराबर ही दिखाई देते हैं एवं विकसित देशों में सामान्यतः बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही, वे अपना अलग परिवार बसा लेते हैं तथा अपने माता पिता से अलग मकान लेकर रहने लगते हैं। इस चलन के पीछे संभवत आर्थिक पक्ष इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जितने अधिक परिवार होंगे उतने ही अधिक मकानों की आवश्यकता होगी, कारों की आवश्यकता होगी, टीवी की आवश्यकता होगी, फ्रिज की आवश्यकता होगी, आदि। लगभग समस्त उत्पादों की आवश्यकता इससे बढ़ेगी जो अंततः बाजार में वृद्धि के रूप में दिखाई देगी एवं इससे इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा वस्तुएं बिकने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इससे आर्थिक वृद्धि दर तेज होगी। विकसित देशों में इस प्रकार की मान्यताएं समाज में अब सामान्य हो चली हैं। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में भी प्रयासरत हैं कि किस प्रकार भारत में संयुक्त परिवार की प्रणाली को तोड़ा जाय ताकि परिवारों की संख्या बढ़े एवं विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़े और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री बाजार में बढ़े। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस प्रकार के विभिन्न सामाजिक सीरियलों को बनवाकर प्रायोजित करते हुए टीवी पर प्रसारित करवाती हैं जिनमें संयुक्त परिवार के नुकसान बताए जाते हैं एवं छोटे छोटे परिवारों के फायदे दिखाए जाते हैं। सास बहू के बीच, ननद देवरानी के बीच, दो बहिनों के बीच, पड़ौसियों के बीच, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े दिखाए जाते हैं एवं जिनका अंत परिवार की टूट के रूप में बताया जाता है, ताकि भारत में भी पूंजीवाद की तर्ज पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल सके। भारत एक विशाल देश है एवं विश्व में सबसे बड़ा बाजार है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यदि अपने इस कुचक्र में सफल हो जाती हैं तो उनकी सोच के अनुसार भारत में उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, इससे विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सीधे सीधे फायदा होगा। इसी कारण के चलते आज जॉर्ज सोरोस जैसे कई विदेशी नागरिक अन्य कई विदेशी संस्थानों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के नागरिकों के लक्ष्य भौतिक (जड़) हो रहे हैं और चेतना कहीं पीछे छूट रही है। केवल आर्थिक विकास अर्थात अर्थ का अर्जन करना ही जैसे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य हो। परंतु, भारत के नागरिक सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के अहसास के प्रति भी सजग दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें चेतना के दर्शन भी होते हैं। अब हम समस्त भारतीय नागरिकों को वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे उक्त वर्णित जाल में नहीं फंसते हुए, हमारे अपने भारतीय व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाते हुए अपनी भारतीय परम्पराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। हमें अपने जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में केवल स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करना चाहिए चाहे वह तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा ही क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर हमारे जीवन में रोजाना उपयोग होने वाले कुछ उत्पादों के नाम यहां पर दिए जा सकते हैं, जिनका उत्पादन सदियों से भारत में ही पर्याप्त मात्रा में होता चला आया है। केवल और केवल भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित इन उत्पादों का उपयोग एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित इन उत्पादों का उपयोग नहीं करने की शपथ ली जानी चाहिए। जैसे, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन औषधियां, टूथपेस्ट, दंतमंजन टूथब्रश, दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स रेजर, बिस्किट चाकलेट दुग्ध उत्पाद ब्रेड, चाय काफी, शीतपेय शरबत चटनी अचार मुरब्बा, आइसक्रीम खाद्यतेल खाद्य पदार्थ, विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु घड़ियां, लेखन सामग्री, जूते चप्पल पॉलिश, तैयार कपड़े, कम्प्यूटर लैपटॉप एवं उपकरण, टेलिकॉम उपकरण, बाम और मरहम, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, स्वचालित वाहन एवं मोबाइल फोन आदि। जब भी बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी ही लाएंगे जैसे तथ्यों को आत्मसात करना चाहिए। इससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी संदेश जाएगा कि भारत अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुका है तथा वैश्विक स्तर पर भारत अब इनके दबाव में आने वाला नहीं है।

सम्पादकीय...

अकबर और टीपू सुल्तान!

चलिए, अब ऑफिशियल हो गया। आरएसएस के प्रचार सचिव, आंबेकर साहब ने खुद अपने श्रीमुख से इसका एलान किया है कि अकबर और टीपू सुल्तान अब ''महान'' नहीं रहे। आजादी के सैकड़ों साल पहले से ये दोनों महान कहलाते आ रहे थे। आजादी के बाद भी पचहत्तर साल तक ये दोनों ही नहीं, वास्तव में और भी बहुत से मुसलमान महान कहलाते रहे थे। पर अब और नहीं। अमृत काल में नहीं। मोदी जी के विकसित होते भारत में नहीं। मोदी जी की भारतीय बना दी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद नहीं। न अकबर, न टीपू सुल्तान और न कोई और मुसलमान, कोई महान-वहान नहीं कहलाएगा। स्कूली किताबों से उनकी महानता को मिटाने की शुरुआत हो गयी है। वह दिन दूर नहीं है जब पक्के तौर पर सैकड़ों साल पीछे का इतिहास बदल जाएगा। आखिरकार, मोदी जी ने अपने रामनाथ गोयनका व्याख्यान में गुलामी की निशानियों को मिटाने का दस साल का ही तो टार्गेट रखा है। यानी मोदीजी की पांचवीं पारी तक अकबर, टीपू, सब गायब नहीं भी हुए तो, पैदल जरूर हो जाएंगे। वैसे और भी बहुत हैं जो खामख्वा में महान बने हुए हैं। काम करके ओह, सॉरी उनके हिसाब से फांद कर के महान बनने वालों में सिर्फ मुसलमान ही थोड़े ही हैं। अकबर से सैकड़ों साल पहले से जो अशोक महान बन बैठा था, उसका क्या? और उससे भी पहले से जो गौतम बुद्ध महान बने बैठे थे, उनका भी क्या? जाहिर है कि अमृत काल में इतिहास की बहुत बहुत दूर तक और गहरी सफाई की जरूरत है। आजादी के बाद के इतिहास की तो और भी गहरी सफाई की। नेहरू, गांधी, आजाद वगैरह से लेकर अम्बेडकर तक, न जाने कौन-कौन महान बने बैठे हैं। अंग्रेजों की विदाई की हड़बड़ी में न जाने कैसे-कैसे लोग महान कहलाने लगे थे। मोदी जी का विकसित होता भारत, कब तक इन फाल्तुओं की महानता का बोझ ढोएगा। अब और ज्यादा दिन नहीं। नागपुर परिवार और उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शाखाएं तो पहले ही इस काम में जुटी हैं। धीरे-धीरे सब का नंबर आएगा, पर सब का नंबर एक साथ नहीं आएगा। फिलहाल मुसलमान यानी अकबर और टीपू सुल्तान! अब प्लीज यह मत पूछिएगा कि अकबर और टीपू सुल्तान ही क्यों? सिंपल है, इन्हें ही महान कहलाने का शौक चर्राया था। शहंशाह, सुल्तान और भी तो हुए थे, पर अपने टैम में महान कहलाए होंगे तो कहलाए होंगे, पर बाद में तो किसी ने महानता की ऐसी लंबी दावेदारी नहीं की। यही बाद तक महानता के सिंहासन पर बैठे रहे थे, सो मोदी जी को दासता के चिह्न मिटाने के लिए, सबसे पहले इन्हीं को अपदस्थ करना था। अब अगर अकबर ने उस जमाने में सर्वधर्म समभाव का राज कायम कर के दिखाया था, उसने न हिंदू न मुसलमान, दीन ए इलाही नाम का नया मेल-मिलाप वाला धर्म चलाया था, तो मोदी जी क्या करें? ऐसे ही अगर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में हराया था और अंत में वह ऐसा पहला शासक बना था जो ब्रिटिश साम्राजी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया था, तो मोदी जी इसका भी क्या करें? इससे मोदी जी की मुश्किल जरूर बढ़ती है, सर्वधर्म समभाव और ब्रिटिश-विरोधी देशभक्ति की पुकारें बीच में आती हैं; लेकिन मोदी जी ऐसी मुश्किलों से डरने वाले नहीं हैं। अकबर और टीपू सुल्तान को महानता की गद्दी खाली करनी ही पड़ेगी। थैंक यू मोदी जी, आंबेकर साहब ने बताया है कि आप अकबर, टीपू सुल्तान वगैरह को सिर्फ महानता की गद्दी से उतार रहे हैं, पूरी तरह से मिटा नहीं रहे हैं। सिर्फ महानता मिटा रहे हैं, उनके नाम नहीं। उन्हें सिर्फ नायक से खलनायक बना रहे हैं, फिल्म से पूरी तरह काट नहीं रहे हैं। थैंक यू इस रहमदिली के लिए। पर हां! शुरुआत स्कूली किताबों में नायक से खलनायक बनाए जाने से ही जरूर रही है, लेकिन बात वहीं तक नहीं रहेगी। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अकबर, टीपू टाइप की महानता से इंकार करने से ही काम नहीं चलेगा। उन्हें बाकायदा राक्षस बताना/ दिखाना पड़ेगा। इसे राष्ट्रवादी होने का सबूत बनाया जाएगा। देशभक्ति की परीक्षा में जै श्रीराम के साथ-साथ, अकबर और टीपू सुल्तान के मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाएंगे। जो जितना जोर से मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, उतना ही पक्का देशभक्त माना जाएगा। मरी सी आवाज में जो मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, वह बहुरूपिया फौरन पकड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो मोदी जी की सरकार अपनी तीसरी पारी में ऐसे देशद्रोही बहुरूपियों के खिलाफ विशेष कानून बनाने में भी नहीं हिचकेगी। वैसे राजद्रोह का कानून तो पहले ही है और उसका काम भी मजबूत है यानी एक बार अंदर किया तो बंदा पांच-छह साल तो जमानत का ही इंतजार करता रह जाता है। फिर अब तो सरकार के सबसे बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बता ही दिया है कि अमृत काल में आतंकवादियों से भी बड़ा खतरा, बुद्धिजीवियों से है यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वालों से। यानी सरकार तो इस विचार की है कि ब्रू ए गोली मार भेजे में, कि भेजा शोर करता है! याद है, सत्या फिल्म के गाने में पिछली सदी के आखिर में ही भेजे के खतरनाक होने के बारे में आगाह कर दिया गया था। फिर भी देश को मोदी जी सरकार आने तक का इंतजार करना पड़ा। पिछली सरकारें अटकती, भटकती, उलझती और झिझकती जो रहीं। पर अब भेजे के खतरे से निपटने के लिए तेज रफ्तार से कदम उठाए जा रहे हैं। चुन-चुनकर पढ़े-लिखे निपटाए जा रहे हैं और जो ज्यादा ही किट-किट करें, जेलों के लिए पठाए जा रहे हैं। और हां! महानों से महानता छीनने की इस मुहिम में हिंदू-मुसलमान खोजने की कोशिश कोई नहीं करे। मोदी जी इस मामले में एकदम सेकुलर हैं। महानता के आसन से सभी को हटाएंगे, हिंदू-मुसलमान सभी को। अकबर, टीपू सुल्तान को, तो गौतम बुद्ध, अशोक को भी, नेहरू, गांधी को भी और पटेल, अम्बेडकर को भी। यह तो शुरुआत है। धीरे-धीरे सब का नंबर आएगा। महानता का आसन मोदी जी को एकदम खाली चाहिए अपने लिए!

लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कमजोर विपक्ष

लोकतंत्र का ध्वंस अचानक विस्फोट के साथ नहीं होता जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले लड़ने का तरीका भूल जाते हैं, तब यह खामोशी में टूटता है। बिहार के चुनावी नतीजे ने विपक्ष को सिर्फ एक राज्य से ही वंचित नहीं किया, इसने भारत को मजबूत लोकतंत्र से भी वंचित कर दिया है। विपक्षी गठबंधन ने बड़े वादे किये थे, पर वह असहमति और व्यक्तियों की आपसी लड़ाई में मात खा गया। बिहार में विपक्ष की हार एक राष्ट्रीय त्रासदी है - ताकतवर भाजपा को चुनौती दे सकने वाला विश्वसनीय विपक्ष देश में नहीं है। यह खालीपन खतरनाक ढंग से गहराता जा रहा है। बिहार में विपक्ष की न कोई योजना थी, न चेहरा था, न कोई सामूहिक संदेश था, ऐसे में अस्तित्व बचाने का संदेश बदलाव के संदेश पर भारी पड़ गया। भाजपा को अपनी ताकत के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के चमत्कृत कर देने वाले संदेश और जीत की प्रतिबद्धता ने सब कुछ तय कर दिया था। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि बिहार वह राज्य है, जिसने आपातकाल के दौरान केंद्रीकृत ताकत को उलट देने का काम किया था। यह दुःखद है कि विपक्ष ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा। अतीत में विपक्ष का प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंसों और सोशल मीडिया पर नाराजगी पर नहीं, बल्कि दमन, जेल, त्याग और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बजाय बदलाव की इच्छा पर आधारित था। एक समय था, जब इंदिरा गांधी अजेय नजर आती थीं और उनकी ताकत ने कानूनी, राजनीतिक और नैतिक चुनौतियों को परास्त कर दिया था, तब विपक्ष किसी एक पार्टी से नहीं, बल्कि आंदोलन से उभरा, वृद्ध जयप्रकाश नारायण ने अपने नैतिक साहस के बल पर इतिहास में जगह बनाई। उन्होंने समाजवादियों, कम्युनिस्टों, परंपरावादी नेताओं, किसान संगठनों, श्रम संगठनों, छात्रों और क्षेत्रीय क्षत्रपों को एकजुट किया और एक राजनीतिक साम्राज्य को सत्ता से बाहर कर दिया। जेपी आंदोलन से जुड़ने वाले अपने राजनीतिक कद और छवि के लिए नहीं, भविष्य के लिए चिंतित थे। उस दौर से आज के विपक्षी नेताओं की तुलना कीजिए। इंडिया गठबंधन में वार्ता मिशन के लिए नहीं, अपनी सीटों के लिए हुई थी। उनके नेता राज्यों को क्षेत्रों की तरह विभाजित कर रहे थे, जैसे राष्ट्रीय राजनीति आपस में बांट लेने का कोई नक्शा हो। हार में भी वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रति चिंतित दिखे, जब राजीव गांधी 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में अपार बहुमत से जीत सत्ता में आये थे, तब ऐसा लगता था कि कोई ताकत उन्हें चुनौती नहीं दे सकती, फिर भी वी.पी. सिंह ने विद्रोह किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता से नायक बनकर उभरे। विद्रोह की उनकी रणनीति बंद कमरे में नहीं बनी थी। उन्होंने देवीलाल और मुलायम सिंह यादव को अपने साथ लिया था। उनके साथ किसान थे, जो राजमार्गों को ठप्प कर दे सकते थे और ऐसे समाजवादी संगठन थे जो शहरों को अपने समर्थकों से भर सकते थे, तब तमिलनाडु में एम. करुणानिधि, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव और पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व जताने की कोशिश नहीं की थी। वे सभी अपने राज्यों को सुरक्षित बनाये रखने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी होने के इच्छुक थे। आज राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता, अब भारतीय राजनीति नेतृत्व के अकाल से गुजर रही है। आज नेतृत्व तो है लेकिन उनमें गंभीरता नहीं है। नारे तो हैं लेकिन उनमें जोश और जुनून नहीं है। वाम राजनीति के पतन से देश में वैचारिकता का बड़ा शून्य आया है। हरियाणा और पंजाब की राजनीति को परिभाषित करने वाले चौटाला और बादल परिवार आज गायब हैं या इतने कमजोर हो गये हैं कि पहचान में नहीं आते। ममता बनर्जी दिल्ली से तभी लड़ती हैं, जब कोलकाता को खतरा पैदा होता है। के. चंद्रशेखर राव तेलंगाना के गौरव की बात करते तो हैं, पर उस सोच को व्यापक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परियोजना में बदलने में रुचि नहीं दिखाते। उत्तर प्रदेश की बात करने वाले अखिलेश यादव व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में हिचकते हैं। आम आदमी पार्टी साझा गठबंधन के साथ जाने को अनिच्छुक है। इस शून्य में अपना वर्चस्व बनाने में भाजपा को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका सांगठनिक तंत्र बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता है। स्थिरता, राष्ट्रवाद, विकास और सुरक्षा के नारों के साथ इसके केंद्रीय चेहरे क्षेत्रीय नेताओं की तुलना में कहीं आगे दिखते हैं। आर्थिक कुलीनतंत्र राजनीतिक एकाधिकार में फलता-फूलता है। सामाजिक ध्रुवीकरण सुविधाजनक औजार बन जाता है। जनता को जब विकल्प नहीं दिखता तब वह जवाबदेही की मांग करना बंद कर देती है। अगर विपक्षी दल अपना पुनरुत्थान चाहते हैं तो वे वंशवादी दांवे, व्यक्तिगत करिश्मे, रक्षात्मक गठबंधन, सत्ता से शिकायत या पार्ट टाइम राजनीति पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें राजनीतिक प्रबंधन के बजाय राजनीतिक आंदोलन पर जोर देना होगा। विपक्ष को एक नेता या नेताओं का समूह चाहिए, जिनकी वैधता त्याग पर आधारित हो। मजबूत और विश्वसनीय विपक्ष के लिए व्यक्तिगत और विचारधारा के स्तर पर बेहतर विकल्प की जरूरत है। एक ऐसा नेता हो जो बेरोजगार युवाओं, छोटे किसानों तथा महिला श्रमिकों के प्रति संवेदना के साथ बोल सकता हो। जो अल्पसंख्यकों को मतदाताओं के रूप में नहीं, अधिकार संपन्न नागरिकों के रूप में देखता हो, ऐसा नेतृत्व ड्राइंग रूम से या वंशानुगत तौर पर नहीं, नीचे से उभरना चाहिए। ऐसा नेतृत्व जो सरकार के खिलाफ टेलीविजन स्टूडियो पर नहीं, सड़कों पर चुनौती दे सकता हो। भारतीय विपक्ष का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वह अल्पावधि में क्षेत्रीय नुकसान सह कर भी साझा वैचारिक मूल्यों पर कितना काम कर सकता है, अगर वह विफल होता है तो लोकतांत्रिक प्रणाली इसी तरह नष्ट होती रहेगी जिससे भाजपा और मोदी अजेय बने रहेंगे। भारतीय लोकतंत्र एकतरफा विमर्श पर हमेशा नहीं चल सकता। विकसित और सुरक्षित भारत के लिए वैकल्पिक विमर्श का उभरना भी जरूरी है।

भर गये सदियों के घाव, आस्था का हो रहा विजयगान, केसरिया ध्वज लहराते ही नया युग शुरू

आज अयोध्या की धरती पर एक ऐसा क्षण उपजा हुआ जो केवल ईंट-पत्थर और वास्तुकला का नहीं, बल्कि पीढ़ियों की आस्था, अनवरत संकल्प और सामूहिक स्मृति का साक्षी बना। जब केसरिया धर्मध्वज गर्व से श्रीराम जन्मभूमि के शिखर पर लहरा उठा, तो वह केवल एक ध्वज नहीं था- वह सैकड़ों वर्ष के अरसे से बंधी हुई वेदना का, अटूट विश्वास का और उन अनगिनत लोगों के संघर्ष का प्रतीक बन गया जो इस पवित्र भूमि को पुनः उसकी गरिमा प्रदान करने के लिये अग्रसर थे। विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर, वैदिक मंत्रों की गूंज और 'जय श्रीराम' के उद्घोष के बीच जो आराधना हुई, वह व्यक्तिगत श्रद्धा से ऊपर उठकर राष्ट्र के सांस्कृतिक स्मरण का साझा अनुष्ठान बन गई। मंदिर के चारों ओर निर्मित परकोटे की शिल्पकला, मुख्य मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए 87 प्रसंग और कॉपर-शिल्प की 79 समृद्ध झांकियां, यह सब केवल स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रामकथा के विविध आयामों का मूर्त रूप है जो हमारी परंपरा की बहुरंगी विविधता को दर्शाते हैं। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा; यह उन अनेकों साधना-यात्रियों, संतों, पुरोहितों, शिल्पकारों, वास्तुकारों, अनुगामियों, श्रमिकों और दानदाताओं की कहानियों का संगम रहा जिनकी तपस्या और त्याग भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। जिन लोगों ने वर्षों, दशकों तक अपनी ऊर्जा समर्पित की, वह आज जहां भी रहे हों, उनके मन में आज निश्चित रूप से आत्म-संतोष का भाव रहा होगा। साधु-संतों की भक्ति-भावनाएं, श्रद्धालुओं की भीड़ और नगरवासियों की आतिथ्य-भावना ने भी यह प्रमाणित किया कि आस्था और सामूहिक विश्वास किस तरह किसी स्थान की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। नया ध्वजारोहण केवल अतीत का जश्न नहीं है; यह भविष्य की दिशा का संकेत भी है। आज की अयोध्या, जहाँ प्राचीन रामकथा और आधुनिक योजनाओं का अप्रत्याशित संगम दिख रहा है, वह इस बात का उदाहरण है कि विरासत और विकास साथ-साथ फल-फूल सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से लेकर आधुनिकीकरण किए गए रेलवे टर्मिनलों, रामपथ और भक्ति-पथ तक, ये सब उस दृष्टि का हिस्सा हैं जो तीर्थ को वैश्विक रूप से सुलभ, सुरक्षित और आदर्श-आधारित बनाने की कल्पना करती है। इस पवित्र क्षण पर, हमें उन अनगिनत नामरहित कर्मयोगियों को भी याद करना चाहिए जिनका श्रम बिना किसी प्रचार-प्रसार के मंदिर निर्माण को साकार करने में सहायक रहा। वे श्रमिक जिनके हाथों ने पत्थरों को संवारा; वे शिल्पकार जिनकी कला ने कथानक को जीवन दिया; वे पुरोहित, संत और पंडित जिनके अनुष्ठानिक ज्ञान ने मार्ग दिखाया; और वे स्वयंसेवक व आयोजक जिनकी रात-दिन की मेहनत ने समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की, इन सबका आभार केवल शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता।

जी-20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के सुझावों की रोशनी

मोदी ने पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल्स, सैटेलाइट डेटा एक्सेस, अफ्रीका में क्षमता निर्माण और ड्रग-टेरर नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे दीर्घकालिक शांति, मजबूती और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता की प्रशंसा की, जिसने कौशल आधारित प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आगे कार्य हो रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन का संकेत स्पष्ट है: दुनिया अब नए खतरे पहचान रही है और उन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रही है। आतंकवाद और ड्रग-तस्करी के गहरे रिश्ते को तोड़ना वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। यदि आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समाज बनाना है, तो ड्रग-पर नियंत्रण करना ही होगा।

ललित गर्ग ।

जी-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र इस बार जिस गंभीर मुद्दे पर केन्द्रित रहा, वह दुनिया के सामने उभरते खतरों की बदलती प्रकृति को स्पष्ट करता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ-साथ ड्रग तस्करी को भी वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानव अस्तित्व के लिए उतना ही घातक बताया जितना किसी संगठित हिंसा को माना जाता है। उनकी यह चेतावनी केवल कूटनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि बढ़ती वैश्विक वास्तविकताओं का सटीक विश्लेषण है। यह तथ्य अब निर्विवाद है कि मादक पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को ईंधन प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है। अरबों डॉलर का यह अवैध व्यापार केवल अपराध जगत को नहीं बल्कि राष्ट्रों की सुरक्षा, समाज की स्थिरता और युवाओं के भविष्य को भी चुन-चुन कर रहा है। मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों को ड्रग-माफिया और उसके आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया आज जिस गति से नए-नए मादक पदार्थों के जाल में फंसती जा रही है, वह वैश्विक चिंता और भी बढ़ाता है। फेंटानाइल जैसे अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स ने अमेरिका में स्वास्थ्य-संकट की भयावह स्थिति पैदा कर दी है, जहां प्रतिदिन अनेक लोग इसके कारण जान गंवा रहे हैं। यह संकट किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन पर मंडरा रहा एक वैश्विक खतरा है। यह मानना भूल होगी कि ऐसे ड्रग्स केवल एक महाद्वीप तक सीमित रह सकते हैं, संगठित तस्करी के नेटवर्क इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि मोदी ने चेताया कि यदि अभी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह त्रासदी अन्य देशों में भी फैल सकती है। ड्रग्स माफिया केवल एक आपराधिक व्यापार नहीं, बल्कि मानव समाज की जड़ों को खोखला करने वाला वैश्विक संकट है। नशे का कारोबार सीमाओं, कानूनों और नैतिक मूल्यों-तीनों को धता बताकर फैल रहा है। यह न केवल युवाओं के भविष्य को निगल रहा है, बल्कि देशों की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। इसलिए, ड्रग्स माफिया का खतरा अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दुनिया भर में नशे का अवैध व्यापार एक विशाल संगठित नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें माफिया, कार्टेल, हथियार गिरोह, आतंकवादी संगठन और भ्रष्ट तंत्र की गहरी सांठगांठ शामिल है। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली है कि कई देशों में यह समानान्तर सत्ता जैसा व्यवहार करता है। अफगानिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, रूस और यूरोप तथा एशिया के अनेक हिस्सों में ड्रग्स कार्टेलों ने शासन प्रणालियों को चुनौती दी है। अनेक जगह तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सरकारें या तो इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाती हैं या फिर समझौते करने को मजबूर हो जाती हैं। मोदी ने इस पर नियंत्रण के लिये दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता व्यक्त की। जी-20 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ड्रग्स के अवैध उत्पादन, वितरण, ऑनलाइन डार्क-नेट व्यापार, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले भुगतान और सीमा-पार तस्करी पर न केवल नियंत्रण करें बल्कि इसके खिलाफ साझा रणनीति भी अपनाएं। मोदी ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए-प्रत्येक देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास, डेटा साझाकरण को बढ़ावा, तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल और साइबर अपराधों के विरुद्ध नई वैश्विक नीति बनाना। एआई का दुरुपयोग आज केवल गलत सूचना फैलाने या साइबर अपराध तक सीमित नहीं रहा; उसके माध्यम से ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री, नकली पहचान, एन्क्रिप्टेड चैनल और तस्करों के गुप्त नेटवर्क को चलाने में भी व्यापक उपयोग होने लगा है। इस पर रोक अब सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं। इस वर्ष का जी-20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद काफी सफल माना गया। यह सफलता केवल उपस्थिति की संख्या में नहीं बल्कि चर्चाओं की गुणवत्ता, मुद्दों की गंभीरता और लिए गए निर्णयों के ठोस स्वरूप में दिखाई दी। बड़े देशों का एक-दूसरे से समन्वय और वैश्विक चुनौतियों को लेकर एकता इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि रही। दुनिया का बदलता भू-राजनीतिक वातावरण, यूक्रेन और मध्य-पूर्व जैसे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और ग्लोबल साउथ की महत्वाकांक्षाएं-इन सबके बीच भी यह सम्मेलन शांत, रचनात्मक और समाधान-उन्मुख रहा। यह संकेत है कि दुनिया के राष्ट्र अब प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं। ड्रग-तस्करी और आतंकवाद जैसे मुद्दे किसी भी देश की सीमाओं में कैद नहीं रह सकते; इसलिए उनका समाधान भी सीमाओं के पार सहयोग से ही संभव है। मोदी के सुझावों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत लंबे समय से सीमा-पार आतंकवाद का शिकार रहा है और दक्षिण एशिया में ड्रग-तस्करी का एक बड़ा ट्रांजिट-पॉइंट भी बनता रहा है। भारत ने तकनीक, कानून और कूटनीति-तीनों स्तरों पर इस खतरे से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे दुनिया सीख सकती है।

भारत का अनुभव बताता है कि ड्रग-नेटवर्क को समाप्त करने के लिए तीन मोर्चों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है-कड़ी सीमा निगरानी, सोशल-मीडिया एवं एआई आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करना, और युवाओं में नशामुक्ति एवं जागरूकता को बढ़ाना। केवल कानून पर्याप्त नहीं; सामाजिक-मानसिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय, प्रभावशाली और केंद्रीय उपस्थिति ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वे आज वैश्विक परिदृश्य के सबसे सशक्त, निर्णायक और भरोसेमंद नेताओं में अग्रणी हैं। अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद विश्व मंच पर नेतृत्व का जो शून्य बन सकता था, उसे मोदी ने अपनी संवेदनशील, दूरदर्शी और कूटनीतिक करिश्मे से भर दिया। ड्रग-तस्करी, आतंकवाद, एआई के दुरुपयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ और मानव-कल्याण जैसे विविध मुद्दों पर उनकी स्पष्ट दृष्टि और व्यावहारिक समाधान ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि भारत न केवल उभरती शक्ति है बल्कि स्थिर और सकारात्मक दिशा दिखाने वाला पथ-प्रदर्शक भी है। उनकी उपस्थिति ने यह भी रेखांकित किया कि बदलती वैश्विक राजनीति में जहां कई राष्ट्र आंतरिक संघर्षों और नीतिगत अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत एक विश्वसनीय, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा है। मोदी का यह उभार केवल भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व का विकल्प देता है जो विकास, शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के नए मॉडल को आगे बढ़ा सकता है और यही आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एकात्म मानववाद के दर्शनशास्त्र को वैश्विक विकास के भविष्य में महत्वपूर्ण बताते हुए दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। मोदी ने पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल्स, सैटेलाइट डेटा एक्सेस, अफ्रीका में क्षमता निर्माण और ड्रग-टेरर नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे दीर्घकालिक शांति, मजबूती और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता की प्रशंसा की, जिसने कौशल आधारित प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आगे कार्य हो रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन का संकेत स्पष्ट है: दुनिया अब नए खतरे पहचान रही है और उन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रही है। आतंकवाद और ड्रग-तस्करी के गहरे रिश्ते को तोड़ना वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। यदि आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समाज बनाना है, तो ड्रग-पर नियंत्रण करना ही होगा। दुनिया की बढ़ती असुरक्षा का मुकाबला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, संयम, शिक्षा और संवेदनशीलता से होगा। जब तक हम नशे के इस वैश्विक खतरे को एक सामूहिक लड़ाई न मानें, तब तक सुरक्षा केवल एक भ्रम बनी रहेगी। समाज को नशे के खिलाफ खड़ा करना आज समय की बड़ी मांग है-क्योंकि यह केवल एक अपराध के खिलाफ संघर्ष नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मुक्ति और स्वस्थ भविष्य देने का संकल्प है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनक ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पॉन्डिचेरी एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/36862)

मतदाता हित में बढ़ायी जाये एसआईआर प्रक्रिया की अवधिः रूचि वीरा

सांसद ने समस्याओं को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन

मुरादाबाद।

समाजवादी पार्टी की सांसद रूचिवीरा ने मुरादाबाद में एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाताओं को हो रही असुविधा और समस्याओं के बारे में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र नहीं पहुंचा रहे हैं और एक ही स्थान पर बैठकर प्रपत्र बांटे जा रहे हैं। सांसद रूचि वीरा ने कहा कि अभी एक हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन अभी बहुत कम काम हुआ है। लोगों को 2003 की लिस्ट अपना नाम ढूंढने के लिए भटकना पड़ रहा है और उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को गणना प्रपत्र के मामले में अनभिज्ञता होने के कारण वह मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। रूचि वीरा ने कहा कि जनपद के विभिन्न पोलिंग स्टेशनो पर 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है और मतगणना प्रपत्र संग्रह की गति अत्यंत धीमी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ मतदाताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं और उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। रूचिवीरा ने कहा कि गणना प्रपत्र भी गलत ढंग से अपलोड किए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकाचार के इस महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लेकर मतदाता हित में एसआईआर की प्रक्रिया की समय अवधि तीन माह बढ़ाई जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए, निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह बीएलओ को प्रशिक्षित करे और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही, मतगणना प्रपत्र संग्रह की गति को बढ़ाने और वेबसाइट पर लिस्ट डाउनलोड करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए। इस दौरान शाने अली शानू, जिला उपाध्यक्ष हाजी तालिब अंसारी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष शीरी गुल, डॉक्टर महमूद, खुशनुद खान, करीम खान, याकूब मलिक, फरीद मलिक, विजयवीर यादव, अमीर अंसारी, आदित्य चौधरी, अब्दुल गनी, असलम पंचायती, शरीफ अंसारी, जिगरी मलिक, फाजिल मालिक आदि लोग मौजूद रहे।

उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लें सभी विभागः मण्डलायुक्त

मुरादाबाद।

मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार मुरादाबाद में आयोजित हुई। बैठक का संचालन योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा किया गया। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा समिति को बताया गया कि विगत मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक 28 अक्टूबर को सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी को प्रेषित किया जा चुका है तथा किसी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः तद्नुसार विगत बैठक की पुष्टि करते हुए एजेण्डावार समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि उद्यमियों की समस्याओं को सभी विभाग गंभीरता से लें। बैठक में मुरादाबाद में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के कि0मी0 164 में, प्रेम वण्डर लाइन के समीप स्थित सम्पार संख्या 41×-ए पर अतिरिक्त दो लेन ऊपरी गामी सेतु के निर्माण हेतु कार्य योजना जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। बैठक में डियर पार्क के संचालन के सम्बन्ध में वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डियर पार्क का पी0पी0 मॉडल सम्भव नहीं है। डियर पार्क के संचालन हेतु रु 120.40 लाख की सोन्दर्यकरण योजना तैयार कर प्रेषित की गयी है , जिसे मण्डलायुक्त द्वारा योजना का निरूपण कराकर इसे पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी। मण्डलायुक्त द्वारा सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि रामगंगा नदी में कूड़ा कचरा एवं अतिक्रमण हटाये जाने एवं उसका चिन्हाकन किये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत करायें। इसके साथ ही गागन नदी के किनारे-किनारे कूड़ा कचरा एवं गन्दगी के सम्बन्ध में भी सिचाई विभाग से रिपोर्ट मागी गयी है। रामगंगा नदी के किनारे अवैध भट्ठीयो के सम्बन्ध में प्रदूषण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 56 भट्ठीयो को बन्द कराया गया है, जिसके सम्बन्ध में मण्डलायुक्त द्वारा उक्त की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। इवेस्ट रिसाईकिलिग व कलेक्सन कराये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम के प्रतिनिधि ई-वेस्ट का डिस्पोजल किस माध्यम से कराया जाता है तथा किसको बेचा जाता है, के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे पाये। इस संबंध में मंडलायुक्त द्वारा निर्देश कृत कार्रवाई से अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए। कांठ रोड पर सड़क के किनारे-किनारे नाला निर्माण कराये जाने के संबंध में एमडी एवं पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि गागन तिराहे के पास कोई भी मार्केट तथा पार्किंग न लगाये इसके साथ ही उद्यमीयो द्वारा मण्डलायुक्त को बताया गया कि हरथला में भी रविवार के दिन बाजार लगता है जिसके कारण वहां पर अत्यधिक जाम लग जाने से आवागमन बाधित होता है इस सम्बन्ध में नगर निगम को रविवार के दिन लगने वाले साप्ताहिक बाजार एवं रोड पर होने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव एमडीए श्री पंकज वर्मा, अपर नगर आयुक्त श्री आशुतोष राय , , श्री संजीव कुमार मण्डी सचिव, श्री पंकज सरन एल0डी0एम0, गोपाल मेहता, राकेश उपाध्याय इन टर्मिनल, लघु उद्योग भारती के मनीष पोपली, दिलशाद हुसैन, तंजील अहमद इत्यादि उद्यमी तथा अधिकारीकरण उपस्थित हुए।

भाषण प्रतियोगिता में आरूषी रस्तोगी ने पाया पहला स्थान

लोकतंत्र की सुरक्षा एवं संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में मीडिया की भूमिका पर बोले विद्यार्थी

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से लोकतंत्र की सुरक्षा एवं संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में मीडिया की भूमिका विषय पर हुई भाषण प्रतियोगिता में आरूषी रस्तोगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संविधान दिवस पर केजीके महाविद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुस्कान प्रजापति द्वितीय व रिपांशु तृतीय स्थान पर रहे। निखिल कुमार, अमोल गुप्ता, दृष्टि चौधरी, शाद मोहम्मद और दीपांशु ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ मीरा कश्यप, डॉ सुनील त्रिपाठी और डॉ दीपक मिश्रा रहे। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ सुनील चौधरी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की धुरी है। यह केवल समाचारों का प्रसारक भर नहीं, बल्कि

जनमत का निर्माणकर्ता, सत्ता का प्रहरी और नागरिकों को जागरूक बनाने वाला सशक्त माध्यम है। मुख्य अतिथि दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि मीडिया शासन के प्रत्येक स्तंभ पर निगरानी रखकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों को उजागर कर यह सत्ता को जवाबदेह बनाता है। सांस्कृतिक समिति प्रभारी डॉ शिव पूजन सिंह यादव ने इस तरह की प्रतियोगिताओं की आवश्यकता पर बल दिया। उपज के अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा ने कहा लोकतंत्र की सुरक्षा इसी बात पर निर्भर करती है कि सूचना स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यपरक हो और यह भूमिका सबसे अधिक मीडिया ही निभाता है। महासचिव कुमार देव ने कहा कि मीडिया संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक संरक्षक है। उपाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि मीडिया नागरिकों के भीतर संवैधानिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखकर राष्ट्र को दिशा देता है। कार्यक्रम का संचालन श्रीराम शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉ अजय कुमार सिंह,डॉ अनिल चौहान, डॉ सुकृति त्यागी, डॉ संजय जौहरी, डॉ गीतिका नागर, डॉ चंद्रभान यादव, डॉ एके राय,डॉ विनय कुमार, डॉ राशिद अहमद, डॉ रितुराज सिंह यादव, डॉ राजकुमार सोनकर, डॉ राजदेव सिंह,डॉ दुर्गेश यादव,डॉ गोविंद नोनिहाल, विनय खन्ना, पुष्प यादव ,सुरबेंदर पाल, अमरदीप सिंह, मौहम्मद आसिफ, दिनेश चंद्र शर्मा,अभिषेक भारद्वाज, प्रेम प्रकाश सक्सेना , मोहम्मद सुहेल खान, रजत शर्मा, वीर भान सिंह, आदि उपस्थित रहे। आभार उपज के सह सचिव डॉ मनोज रस्तोगी ने व्यक्त किया।

ट्रेन से कटकर छात्र की मौत

मुरादाबाद। जनपद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में सुबह कोचिंग जा रहे एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना मिलक कामरु गांव के पास हाइवे रेल लाइन पर हुई। जगतपुर रामराय निवासी 18 वर्षीय अजय कुमार पुत्र रामबहादुर सुबह गुलाबबाड़ी स्थित कोचिंग सेंटर जा रहा था। वह गांव से जंगल के रास्ते जीरो प्वाइंट की ओर बढ़ रहा था और रेलवे पटरी पार करते समय रामपुर की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।तेज आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अजय का शव खून से लथपथ पटरी के पत्थरों पर पड़ा था, रोटी और बैग दूर बिखरे पड़े थे। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जीरो प्वाइंट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया। अजय के दादा-दादी और ग्रामीण रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे। परिवार वालों ने बताया कि अजय कुमार बीए का छात्र था और घर का इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई के साथ-साथ खेती-किसानी में भी हाथ बंटाता था। परिवार में उसकी मां शांति देवी और बहनें अंजलि व सुषमा हैं। अजय की मौत से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

डीएम ने ईवीएम वेयरहाउस का किया मासिक निरीक्षण

मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मुरादाबाद शहर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वेयरहाउस में उपलब्ध संसाधनों एवं सुरक्षा मानकों का सत्यापन किया साथ ही उन्होंने परिसर में साफ सफाई को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम भी मौजूद रहीं।

एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कलेक्ट्रेट पर गरजे किसान

मुरादाबाद। (वेबवार्ता) भाकियू (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाकियू पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की मांग की। भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि, संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली आंदोलन को 5 साल पूरे हो गए है। इस आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान गंवाई। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का वादा किया था। लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया। किसान नेताओं ने मांग उठाई कि आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए आंदोलन को लेकर सरकार ने जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज कराए थे वो सभी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकल में धान जगह-जगह तुल रहा है। क्रय केंद्रों पर किसान का धान नहीं तुल रहा है बल्कि बिचौलियों का धान तुल रहा है।

युवाओं को दिलाई संविधान की शपथ

मुरादाबाद।

मेरा युवा भारत के तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन युवाओं को संविधान की शपथ महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा दिलाई गई। नवनिर्मित संविधान पार्क के प्रांगण में किया गया किया गया जैसा कि विदित है आज संविधान दिवस पूरे देश मे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद में संविधान दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन मेरा युवा भारत सरकार के विभाग द्वारा किया गया विभाग के अधिकारी उप निदेशक अंकित कुमार ने बताया कि आज के आयोजन में शहर के महापौर विनोद अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त एवं महापौर द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया। जहां महापौर विनोद अग्रवाल ने युवाओं से संविधान

निर्माताओं चिंतन करने के लिए कहा वहीं मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने युवाओं में समानता के अधिकार को विशेष तौर पर महत्व देने के लिए आगे आने को कहा।

इस कार्यक्रम में मेरा युवा भारत के 500 से अधिक युवाओं ने संपूर्ण जनपद से प्रतिभाग किया इस कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र बलून फेस्टिवल रहा संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माय भारत एवं संविधान के संदेश से ×00 सजे हुए थे और मंडल आयुक्त एवं महापौर ने इन गुब्बाड़ों को हवा में छोड़ा यहां मौजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस किया इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के 5 प्रतिभावान युवा वक्ताओं ने अपनी विशेष प्रतिभा से युवाओं को प्रभावित किया कार्यक्रम में पर्वतारोही विवेक आनंद ने यह बताया कि कैसे पर्वतों से भारत एक महान भारत बनता है उसमें पर्वतों की क्या भूमिका है वहीं लॉ की छात्रा रूजल पाठक ने युवाओं को संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ दीपक मेहंदी दत्ता प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ने किया उन्होंने युवाओं को संविधान और विज्ञान दोनों के गहन अध्ययन से जागरूक होने का आह्वान किया कार्यक्रम के सफल आयोजन में जनपद मुरादाबाद के नगर निगम का विशेष योगदान प्राप्त हुआ और नगर निगम के सहयोग से संविधान साहित्य वाटिका को आम जन तक पहुंचाने का भी यह प्रयास रहा। इस कार्यक्रम में प्रतिभावान युवाओं को अशोक स्तंभ के चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया कार्यक्रम में मेरा युवा भारत मुरादाबाद के समस्त स्टाफ जोगेंद्र ,रंजीत सैनी ,चंद्र सिंह संचल, अमित कुमार, विकास ,ने अपनी विशेष भूमिका निभाई।

दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून ट्रायल सफल, टूरिम को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। दिल्ली में मनोरंजन और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार हॉट एयर बैलून का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. राजधानी के प्रसिद्ध बांसेरा पार्क में हुए इस ट्रायल को देखने खुद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे थे. उनके साथ डीडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने बैलून की सुरक्षा और संचालन का बारीकी से निरीक्षण किया. ट्रायल के दौरान हॉट एयर बैलून को करीब 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिलहाल इसे 200 फीट तक

उड़ने की अनुमति दी है. लेकिन शुरुआती चरण में सुरक्षा जांच को पुख्ता करने के लिए इसे 100 से 150 फीट तक ही उड़ाया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती टेस्ट पूरी तरह सफल रहे हैं डीडीए ने बताया कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता रहा तो यह सेवा एक सप्ताह के भीतर आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं. यह सेवा सिर्फ बांसेरा पार्क तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली के 4 प्रमुख स्थानों पर शुरू की जाएगी. असिता पूर्वी पार, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बांसेरा पार्क, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज इन जगहों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है. अंदाजा है कि हॉट एयर बैलून राइड की कीमत करीब 3500 रुपये रखी जा सकती है. एक बार में 4 लोग बैलून में सवार हो सकेंगे. हर राइड करीब 7 से 12 मिनट तक हवा में रहने का रोमांच देगी. ट्रायल के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह कदम उन वादों को पूरा करता है जिनमें दिल्लीवासियों को नए और रोमांचक मनोरंजन विकल्प देने की बात कही गई थी. उन्होंने बताया कि डीडीए ने कई बड़े पार्क विकसित किए हैं.

---

23 बीएलओ की मौत के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई सुनवाई

चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब

नई दिल्ली।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित की है। केरल के मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर को तमिलनाडु के मामलों की सुनवाई 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। बिहार के एसआईआर से संबंधित संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। केरल एसआईआर मामला स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर प्रक्रिया के स्थगन के कारण उत्पन्न हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया

कि इस मामले से संबंधित याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय में पहले ही दायर की जा चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाए रखा है, 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और 50 प्रतिशत से अधिक पहले ही डिजिटल रूप से जमा कर दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने केरल के एसआईआर के संबंध में एक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, और सुनवाई उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है। तमिलनाडु एसआईआर मामले से जुड़े सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होंगी और 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने होंगे। सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 23 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब मांगा है और राज्य चुनाव आयोगों और चुनाव आयोग दोनों से जवाब देने का आदेश दिया है।

रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी पर भारी बवाल, पुलिस पर पथराव, चक्का जाम

भोपाल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. घटना के पांच दिन बाद भी आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. हिंदू समाज ने गौहरगंज में विशाल धरना-प्रदर्शन कर न्याय की मांग की. महिलाओं ने भी फांसी की सजा की मांग करते हुए धरना दिया. वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह-जगह रैलियां निकाली गईं. इस प्रदर्शन के दौरान गौहरगंज में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई है कि मस्जिद के गेट के सामने पथराव कर दिया. इधर सीएम मोहन यादव ने रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडेय को हटा दिया है. उनकी जगह पर आशुतोष को रायसेन का नया एसपी बनाया गया है. दरअसल पुलिस को ज्ञापन देने के बाद उग्र भीड़ ने मस्जिद के सामने पथराव किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की. नर्मदापुरम के आईजी और डीआईजी ने भी इलाके का दौरा किया है.

मानवाधिकारों का उल्लंघन- एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस जघन्य अपराध को मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए रायसेन के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है. आयोग ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है और एम्बुलेंस में देरी पर नाराजगी जताई है. एनएचआरसी ने निर्देश जारी किए हैं कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, आरोपी की गिरफ्तारी और सभी कानूनी प्रक्रियाएं फौरन पूरी की जाएं. रिपोर्ट की कॉपी डीजीपी भोपाल को भेजी जाए. एनएचआरसी ने मामले की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला किया है. बच्ची का एम्स भोपाल में ऑपरेशन हुआ है और हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

आरोपी पर 30 हजार का इनाम

नर्मदापुरम रेंज के डीआईजी प्रशांत खरे ने आरोपी सलमान पर 30,000 का इनाम घोषित किया है. 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 20 विशेष टीमें जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं. डीआईजी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

हैदराबाद में मोदी ने सैफरान के विमान इंजन मरम्मत केंद्र का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को फ्रांसीसी विमानन कंपनी सैफरान के विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और देखभाल (एमआरओ) संयंत्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। सैफरान की इकाई सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) का यह संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र वर्ष 2026 से परिचालन में आ जाएगा। इस परियोजना में 1,300 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया गया है। यह संयंत्र विमानों की लीप इंजन की सर्विसिंग के लिए है। इन इंजनों का इस्तेमाल एयरबस ए320 निओ और बोइंग 737 मैक्स जैसे पतले आकार वाले वाणिज्यिक विमानों में किया जाता है। लीप इंजन का निर्माण सीएफएम इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जो सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन और जीई एयरोस्पेस का संयुक्त उपक्रम है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है और घरेलू एयरलाइनों ने अब तक 1,500 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है। एसएईएसआई के संयंत्र में पूर्ण क्षमता हासिल होने पर हर साल 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग की जा सकेगी। इससे देश के तेजी से बढ़ते नागर विमानन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, पांच की मौत

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले के ढखेरवा-गिरिजापुरी बैराज रोड पर भजियापुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर के किनारे बने पक्के नाले में गिर गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। यह हादसा पढ़ुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुआ। पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) ने बताया कि मृतकों की पहचान जितेंद्र (23), घनश्याम (25), लालजी (45), अजीमुल्ला (45) और सुरेंद्र (56) के रूप में हुई है। ये सभी बहराइच जिले के रहने वाले थे। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिंह ने कहा, हादसे में जीवित बचे व्यक्ति की पहचान सूरज उर्फ बब्बू के रूप में हुई है, जो बहराइच का ही रहने वाला है और गाड़ी चला रहा था। उसे रमियाबेहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। पुलिस के मुताबिक, सभी छह लोग एक दोस्त के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद बहराइच लौट रहे थे।

आंध्र प्रदेश में गैस टैंकर में विस्फोट, दो लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के येलमपाडु में बुधवार को एक टाइल फैक्टरी में एक गैस टैंकर में विस्फोट होने से दो श्रमिकों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। श्री कालाहस्ती उप-विभागीय पुलिस अधिकारी नरसिम्हा मूर्ति ने बताया कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से भरे जाने वाले बड़े टैंकर में सुबह करीब 11.30 बजे उस समय विस्फोट हो गया, जब उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके रिसाव की जांच की जा रही थी। मूर्ति ने पीटीआई- को बताया, टैंकर में विस्फोट होने से दो श्रमिकों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। टैंकर में विस्फोट उस समय हुआ जब रिसाव की जांच के लिए नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि दोनों श्रमिकों की मौत सिर में चोट लगने से हुई और इस सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।

41 नक्सलियों ने छोड़े हथियार, 32 पर था 1.19 करोड़ का इनाम

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 महिलाओं समेत कुल 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, 32 नक्सलियों पर कुल 1.19 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार को 12 महिलाओं समेत कुल 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी- सीएम ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पीछे असली मंशा एनआरसी है।

संविधान दिवस के अवसर पर रेड रोड स्थित बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। एक दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ममता ने कहा कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो, तो लोगों को संविधान से मिले मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। सीएम बनर्जी ने कहा कि संविधान राष्ट्र की रीढ़ है, जो भारत की संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की विविधता को

कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस संविधान दिवस पर मैं हमारे महान संविधान और भारत में हमें जोड़ने वाले महान दस्तावेज के प्रति महान सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले राज्यसभा सचिवालय ने सदस्यों को संसदीय शिष्टाचार और अनुशासन को लेकर नया बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में सदन की गंभीरता बनाए रखने के लिए नारेबाजी समेत जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू जैसे शब्दों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, अब आप सोचिए, देश में क्या चल रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे। जय हिंद और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। ये हमारी आजादी के नारे हैं। जय हिंद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इससे जो टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। वहीं, ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि वो जितने आरोप लगाना चाहें, लगा लें। उन्होंने कहा कि क्या वो देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती हैं? भाजपा नेता ने कहा कि क्या वो एक और शाहीन बाग बनाना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने ठान लिया है कि वो पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी को कोई सुनता ही नहीं है।

संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़।

संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा विधानसभा पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही संविधान की मूल भावना है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है और सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज संविधान पूरी तरह सुरक्षित

है और सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास संविधान की भावना का सच्चा प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे ने संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि देशहित

राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना ही संविधान की मूल भावना – मुख्यमंत्री

और संविधान की गरिमा सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से संविधान में निहित मूल कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं को संविधान की समझ के साथ समाज और देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री राजेश नागर सहित अनेक विधायक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

औपनिवेशिक मानसिकता त्यागने, राष्ट्रवादी सोच अपनाने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है संविधान : द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि संविधान औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने और राष्ट्रवादी सोच अपनाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। उन्होंने 'संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत दुनिया के लिए विकास का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। उनका कहना था, ''हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे व्यक्तिगत, लोकतांत्रिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। संविधान औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने और राष्ट्रवादी सोच को अपनाने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। उन्होंने कहा, ''25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। महिलाएं, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना था कि संविधान दिवस मनाने की परंपरा आरंभ करने की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वो कम है। राष्ट्रपति ने नौ भाषाओं - मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में संविधान के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किया गया।

विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है संविधान: सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि न्याय, समता और बंधुता भारत के संविधान की मूल भावना है। इसे बनाये रखना सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, संविधान दिवस की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। न्याय, समता और बंधुता भारत के संविधान की मूल भावना है। सीएम योगी ने कहा है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अद्भुत दृष्टि, प्रखर विचार और अथक परिश्रम से निर्मित हमारा संविधान विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि संविधान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति का आधार होने के साथ ही हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर भी प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर के महान योगदान को याद करना है।

भीमराव अंबेडकर का दिया सबसे बड़ा अधिकार वोट आज खतरे में- अखिलेश

लखनऊ।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमने देखा कि भाजपा ने आज सुबह संविधान दिवस मनाया। लेकिन, संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं ने पहुंचाया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया सबसे बड़ा अधिकार, वोट, खतरे में लगता है। क्योंकि, वे अलग-अलग बहानों से लाखों लोगों को उनके वोट के अधिकार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

यूपी में लाखों लोगों के वोट काटने के लिए साजिशें और अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश के नाम पर वे पश्चिम बंगाल में साजिशें रच रहे हैं। सेक्युलरिज्म को भूल जाइए। वे सेक्युलरिज्म का असली मतलब

नहीं समझते। उनकी सरकार में कोई सोशलिस्ट नहीं बचा है, अब कोई सेक्युलरिज्म नहीं है और स्ट्रक के साथ उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल दिया है। अखिलेश यादव 120 बहादुर 120 बहादुर मूवी देखने पहुंचे। मूवी भारत-चीन युद्ध पर आधारित है। इसमें फरहान अख्तर ने परमवीर चक्र सम्मानित मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव के मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीति के जानकार इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि मूवी में अहीर समुदाय के इतिहास और उनकी बहादुरी को दर्शाया गया है।

संविधान के सिद्धांतों को सुनियोजित ढंग से कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह संविधान पर होने वाले हर प्रहार का सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, लेकिन आज वे पहचान खतरे में है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा और आरएसएस का संविधान के प्रति आदर दिखाना सिर्फ ढोंग है। संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स पर पोस्ट किया, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा यह कि चाहे कोई किसी

भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने कहा, आइए, हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''बाबासाहेब डॉ अंबेडकर व पंडित नेहरू ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है।

न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आज ये पहचान खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''जब संविधान लागू हुआ था, तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है।

इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडम्बना यह है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया, ''11 दिसंबर, 1948 को इन्हीं लोगों ने रामलीला मैदान में बड़ा सम्मेलन करके बाबासाहेब अंबेडकर का पुतला भी फूंका था। आरएसएस ने केवल संविधान और तिरंगे का विरोध ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी राज में जब स्वाधीनता सेनानी जेलों में थे तो आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज उसी आरएसएस की लाल किले से तारीफ करते हैं, जबकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद 30 जनवरी 1948 को आरएसएस पर पहला प्रतिबंध सरदार पटेल जी ने लगाया था।